GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO : 51
(TO BE ANSWERED ON THE 12th December 2022)

UDAN SCHEME FOR DOMESTIC TRAVEL IN THE STATE OF ODISHA

*51. SMT MAMATA MOHANTA

Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:-

(a) the details of the airports selected/proposed under the Ude Desh ka Aam Nagrik (UDAN) scheme for domestic travel in the State of Odisha;
(b) the airports which are ready and to be developed under UDAN scheme in Odisha;
(c) whether there have been demands for connecting more airports from Odisha, if so, the details thereof including destinations already connected and those which are in the pipeline; and
(d) the status of the survey conducted with regard to the airstrips under UDAN scheme in the State of Odisha?

ANSWER

MINISTER OF CIVIL AVIATION

(Shri Jyotiraditya M. Scindia)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

*****

STATEMENT IN RESPECT OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 51 REGARDING "UDAN SCHEME FOR DOMESTIC TRAVEL IN THE STATE OF ODISHA" TO BE ANSWERED ON 12.12.2022.

(a) & (b): Ministry of Civil Aviation (MoCA) has launched Regional Connectivity Scheme (RCS) - UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) on 21-10-2016 to enhance regional air connectivity from unserved and underserved airports in the country and making air travel affordable to the masses. UDAN is a market driven scheme. Interested airlines based on their assessment of demand on particular routes, submit their proposals at the time of bidding under UDAN.

Eighteen unserved Airstrips namely Amarda Road, Angul, Barbil, Birasal, Gudari, Hirakund, Jayakpur, Jeypore, Lanjigarh, Nawapara, Padampur, Rairangpur, Raisuan, Rangeilunda, Sukinda, Theruboli, Tushra and Utkela, are available in the UDAN Scheme document for the State of Odisha.

Five airports namely Jeypore, Utkela, Rourkela, Jharsuguda and Rangeilunda have been identified for up-gradation for the operation of flights under UDAN. Jharsuguda and Jeypore airports have been developed / upgraded and UDAN flights have commenced therefrom.

(c): MoCA has been receiving requests / demands from various quarters including States / UTs for more air connectivity. Selection of airlines is done through a transparent e-bidding process under UDAN.
In future rounds of bidding, any airline bids for connecting airports in Odisha to other domestic destinations in the country, the same shall be considered for the award as per the provisions of UDAN scheme document.

(d): Interested airlines undertake due diligence of particular route and based on their assessment of demand/airstrips on particular routes, before submitting their proposals at the time of bidding under UDAN.

*****

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

मौखिक प्रश्न संख्या :51

सोमवार,12 दिसम्बर, 2022/ 21 अग्रहायण,1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ओडिशा राज्य में घरेलू यात्रा के लिए 'उड़ान' योजना

***51 श्रीमती ममता मोहंता:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओडिशा राज्य में घरेलू यात्रा के लिए 'उडे देश का आम नागरिक' (उड़ान) योजना के तहत चयनित/प्रस्तावित हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिशा में 'उड़ान' योजना के तहत कितने हवाईअड्डे विकसित हो चुके हैं और कितने विकसित किए जाने हैं;

(ग) क्या ओडिशा से और हवाईअड्डों को जोडने की मांग की गई है, यदि हां, तो पहले से जुडे गंतव्य स्थलों और योजनाधीन गंतव्य स्थलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ओडिशा राज्य से 'उड़ान' योजना के तहत हवाई पट्टियों के संबंध में किए गए सर्वेक्षण की स्थिति क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ): वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

'ओड़िशा राज्य में घरेलू यात्रा के लिए उड़ान योजना' से संबंधित राज्य सभा के दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 के मौखिक प्रश्न संख्या 51 के उत्तर से संबंधित वक्तव्य।

(क) तथा (ख) : नागर विमानन मंत्रालय ने देश के अपरिचालित एवं अल्प परिचालित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय विमान सम्पर्क को बढावा देने एवं जनसाधारण के लिए विमान यात्रा को किफायती बनाने के उद्देश्य से दिनांक 21.10.2016 को क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) का शुभारंभ किया था। उड़ान बाजार चालित योजना है। उड़ान के अंतर्गत बोली के समय, इच्छुक एयरलाइनें किसी मार्ग विशेष की मांग के अपने मूल्यांकन के आधार पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं।

ओडिशा राज्य के लिए, उड़ान योजना दस्तावेज के अंतर्गत अठारह अप्रचालित हवाईपट्टियां नामत: अमरदा रोड, अंगुल, बारबिल, बिरासल, गुदारी, हीराकुंड, जायकपुर, जैपोर, लांजिगढ़, नवापाढ़ा, पदमपुर, रैरंगपुर, रायसुयान, रंगेलुंडा, सुकिंदा, थेरूबोली तुशरा तथा उत्केला उपलब्ध हैं।

जैपोर, उत्केला, राउरकेला, झारसुगुडा तथा रंगेलुंडा नामक पांच हवाईअड्डों का निर्धारण उड़ान योजना के अंतर्गत उड़ानों के प्रचालन के उन्नयन के लिए किया गया है। झारसुगुडा तथा जैपोर हवाईअड्डों का विकास / उन्नयन कर लिया गया है तथा वहां से उड़ान योजना के अंतर्गत उड़ानें प्रारंभ हो गई हैं।

(ग): नागर विमानन मंत्रालय को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित विभिन्न पक्षों से और अधिक विमान सम्पर्क के अनुरोध/मांग प्राप्त हो रही है। एयरलाइनों का चयन, उड़ान के अंतर्गत, पारदर्शी ई-बोली के माध्यम से किया जाता है।

भविष्य में आयोजित की जाने वाली बोली के चरणों में, उड़िशा में स्थित हवाईअड्डों से देश के अन्य गंतव्यों से सम्पर्क के लिए, यदि किसी एयरलाइन से बोली प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो उस पर उड़ान योजना दस्तावेज के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड जारी करने के लिए विचार किया जाएगा।

(घ): इच्छुक एयरलाइनें, उड़ान योजना के अंतर्गत किसी मार्ग विशेष के लिए अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व, उस मार्ग विशेष पर मांग/के तथा हवाई पट्टी के मूल्यांकन के पश्चात सम्यक उत्साहपूर्वक कार्य करती है।

****

श्रीमती ममता मोहंताः सर, अमरदा रोड एयरस्ट्रिप विकसित करके उत्तर ओडिशा में एक एयरपोर्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक क्या प्रयास किया गया है? कृपया इससे संबंधित एक सम्पूर्ण विवरण प्रदान करें और जो ज़मीन रक्षा विभाग की है, इसको राज्य सरकार को देने का प्रयास क्या है?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधियाः सर, यह प्रश्न अमरदा एयरस्ट्रिप के विषय में है। यहां डिफेंस के साथ हमारी चर्चा हुई है। स्टेट गवर्नमेंट को ज़मीन आवंटित की गई है। स्टेट गवर्नमेंट से उस ज़मीन के लिए रक्षा मंत्रालय को 26 करोड़ रुपये दिलवाने हैं। यह स्टेट गवर्नमेंट का एयरपोर्ट है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट को ही डेवलप करना होगा।

श्रीमती ममता मोहंताः सर, 13 जनवरी, 2023 से ओडिशा में पुरुष हॉकी विश्व कप शुरू होगा। टूर्नामेंट के मैच राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में भी खेले जाएंगे। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी और दर्शक एकत्रित होंगे, जिसके लिए राउरकेला एयरपोर्ट का विस्तार होना ज़रूरी है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि राउरकेला एयरपोर्ट का काम कब तक समाप्त होगा और पैसेंजर्स के लिए वहां क्या सुविधाएं की गई हैं?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधियाः सभापति महोदय, राउरकेला एयरपोर्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एयरपोर्ट है। यहां हमारी विचारधारा यह थी कि इसका विकास और प्रगति करना अति आवश्यक है। इस एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए सेल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक मसौदे पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वैसे भी एटीआर के डेवलपमेंट के लिए इस एयरपोर्ट पर करीब 28 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। राउरकेला एयरपोर्ट पर सात करोड़ रुपये के नए ऐप्रन बने हैं। महोदय, आपके द्वारा मुझे हाउस को बताते हुए खुशी हो रही है कि यह कार्य समाप्त हो चुका है। यहां दो करोड़ रुपये की बाउंड्री वॉल का भी पूर्ण क्रियान्वयन हो चुका है। इसी के साथ रीसर्फेसिंग ऑफ रनवे का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। 15 दिसंबर तक कन्स्ट्रक्शन ऑफ पैरामीटर वॉल का कार्य भी पूरा हो जाएगा। हमने एक्सटेंशन ऑफ टर्मिनल बिल्डिंग के लिए छह करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो 15 दिसंबर, 2023 तक समाप्त हो जाएगा। माननीय सदस्य महोदया ने कहा कि राउरकेला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेल का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए एयरपोर्ट को ऑपरेशनल बनाने के लिए दो कदम उठाने जरूरी हैं। पहला, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच सीएनएस और एएनएस के हस्ताक्षर होने बहुत जरूरी हैं। मैंने दोनों विभागों को यह निर्देश भी दिए थे कि जल्द इस पर हस्ताक्षर हों और मुझे माननीय सदस्या को सूचित करते हुए खुशी है कि आज सुबह दस बजे सेल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में सीएनएस और एएआई एग्रीमेंट के बीच में हस्ताक्षर हो चुके हैं। सर, मैं एक और चीज़ सूचित करना चाहता हूं कि अब केवल डीजीसीए का इन्स्पेक्शन बाकी है। छोटे प्लेन की 2बी कैपेबिलिटी, 2सी एयरपोर्ट में परिवर्तित करने के लिए..., ताकि वहां पर एटीआर लैंड कर पाए, जो आपकी भी इच्छा है। उड़ान में जो बिड्स दिए गए हैं, एलायंस एयर को, एटीआर भुवनेश्वर और राउरकेला के बीच में और

बिग चार्टर को कोलकाता और राउरकेला के बीच में दिया है। वह एक छोटा प्लेन है और हम लोग दोनों का क्रियान्वयन करेंगे। यह लाइसेंस डीजीसीए द्वारा एटीआर के लिए दिया जाएगा।

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, under UDAN Regional Connectivity Scheme, 28 seaplane routes and 115 helicopter routes have already been sanctioned. I would like to know from the hon. Minister as to what the status of these UDAN operations is. In Vishakhapatnam, there was a similar proposal in cruise terminal for promotion of tourism. I would like to know this from the hon. Minister.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, what is extremely important in India today -- I would like to seek the indulgence of the Chair -- is that we have a very effective international to domestic connectivity. We have very effective domestic Tier-I to Tier-II connectivity. But, certainly, the concentration has to be on last-mile connectivity and that is very clearly the question the hon. Member has focussed on because last-mile connectivity through civil aviation is the key. That last-mile connectivity can only be given by small planes, less than 20-seater, by seaplanes and by helicopters. With that in mind, our Ministry has tweaked the UDAN Scheme. The UDAN Scheme used to be for sub-90 seater planes. We have now introduced a new mechanism under UDAN, which is a Small Aircraft Scheme only dedicated to less than 20-seater aircraft. Under that Small Aircraft Scheme, which we have launched in UDAN 4.2, I am very pleased to inform the House that a total of 132 routes have been awarded. Out of these, 16 are helicopter routes; 50 are seaplane routes and 66 are fixed wing routes. So, many States will get the benefit of last-mile connectivity through this UDAN Small Aircraft Scheme across the geography, from Telangana to Lakshadweep. All the way to our hill States and North-Eastern States and to Assam, we have provided connectivity through these awards that we have given in this latest round of UDAN 4.2.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I would request the hon. Minister to kindly inform this House when the air connectivity between Kolkata, Malda, Balurghat and Cooch Behar shall commence.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, as I have mentioned before, the civil aviation sector is a de-regulated sector. It is completely incumbent upon the airlines to choose their routes. Certainly, through UDAN, we do offer airports that are *alp-sevit* or *a-sevit*, either under-served or not served, airports. The hon. Member's Party delegation had come to meet me. We have also informed the hon. Member's Party

representatives about certain requirements of land in West Bengal. We have also requested if they can lower their VAT on ATF, which 16 States across the country have already lowered, in addition to the 12 States that had only charged between 1 and 4 per cent. So, 28 States today charge VAT on ATF of only 1 to 4 per cent, and there are only eight States left in the country that charge exorbitant VAT on ATF between 20 and 30 per cent. I would urge the Member to request his Government in West Bengal to lower that rate. If he does, it will, certainly, lead to a new impulse for greater connectivity into West Bengal and even greater refuelling in West Bengal.

SHRI VAIKO: Sir, the hon. Minister has given a brief description about the steps being taken for Odisha. I would like to know from the hon. Minister whether the same yardstick will be applied to my State, Tamil Nadu.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Of course, Sir, without doubt. It is our job, our responsibility to make sure that every State across the length and breadth of India emerges in the area of civil aviation. I would like to inform the hon. Member that in the last eight years, under the leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, where we had only 74 airports until 2013-14 in our country, we have added 71 airports, waterdromes and heliports, taking it to 145, and I commit to the hon. Member also that this number will surpass 200 in the next five years thereby increasing air connectivity in our country.

Also, regarding the airport in Chennai, which is very much a concern for our citizens in Tamil Nadu, we are very aggressively looking at that airport in Parandur also, so that we can provide a new Greenfield Terminal in Chennai.

MR. CHAIRMAN: And, that commitment is through the Chair. Now, Shri Biplab Kumar Deb.

श्री बिप्लब कुमार देब: ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि त्रिपुरा के कैलाशहर में एक नए एयरपोर्ट के लिए त्रिपुरा सरकार ने जमीन देने की व्यवस्था की है और आपके दफ्तर से त्रिपुरा सरकार को कम्युनिकेट भी किया गया है कि इस जमीन की देखभाल करने में 6 महीने का समय लगेगा।

MR. CHAIRMAN: Please put pointed question.

श्री बिप्लब कुमार देब: मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके दफ्तर से कब तक कैलाशहर में एयरपोर्ट की अनुशंसा की जाएगी?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधियाः सर, यह प्रश्न ओडिशा पर था। मैं बिप्लव देब जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि वे पूर्व में भी बेहद उत्सुक थे कि इस एयरपोर्ट का विकास हो, हम इस क्वेश्चन ऑवर के बाद मिलेंगे और इस पर विश्लेषण करके आगे का रास्ता तय करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Now, Q. No. 52.